(c) Export of beef and veal is banned under import-export policy, 1992—97. Hence, all the beef produced is for domestic consumption.

बिहार द्वारा यूरिया की मांग

500. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा चालू रबी के मौसम में कुल कितनी यूरिया खाद की मांग की गई है तथा इस मांग का माहवार ब्यौरा क्या है,

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को की गयी यूरिया, खाद की आपूर्ति का माहवार ब्यौरा क्या है,

(ग) बिहार में यूरिया खाद की कमी को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति न करने के लिए, जिसका फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं,

(घ) क्या सरकार द्वारा मामलें की जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है, और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) राज्य सरकार और उर्वरक उद्योग के परामर्श से कृषि मंत्रालय ने रबी 1995-96 मौसम के लिए बिहार में यूरिया की आवश्यकता 6.00 लाख टन आंकी है। भारत सरकार द्वारा यूरिया की मांग का माहवार मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(ख) गत वर्ष के समकालीन मौसम के दौरान यूरिया को बिक्री की प्रवृत्ति के आधार पर राज्यों की माहवार आपूर्तियां सुनिश्चित की जाती है। अक्तूबर, 1995- जनवलरी, 1996 अवधि के दौरान बिहार राज्य में यूरिया के माहवार प्रेषण और संचयी उपलब्धता निम्नानुसार थी:

रबी 95-96 (000 टन)

1.10.95 **का अवशेष अवधि**	**भण्डार प्रेषण**	***माह के प्रेषण** 5.1.97 **दौरान संचयी उपलब्धता**	**संचीयी बिक्री**
अक्तूबर, 95 तक	77.08	129.05	75.46
नवम्बर, 95 तक	99.32	228.37	163.58
दिसम्बर, 95 तक	160.38	338.75	315.44
जनवरी, 96 तक	150.79	539.54	436.65

* उपलब्धता में 1.10.95 के अनुसार अथशेष भण्डार और उस अवधि के दौरान किए गए प्रेषण शामिल हैं।

(ग) इस समय यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिसके विक्रय एवं लाने-ले-जाने पर सरकार का वैधानिक नियन्त्रण है। रबी 95-96 के दौरान इसकी प्रति माह बिक्री उपलब्धता से कम थी। अत: राज्य में यूरिया की कुल मिला कर कोई कमी नहीं थी। राज्य में उर्वरकों का वितरण सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ड़) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हीरों का खनन

501. **श्री राघवजी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रामपुर जिले में स्थित देवयोग क्षेत्र में हीरों के खनन संबंधी कोई योजना 31 जनवरी, 1996 तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्य है तथा केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उत्पादों के भंडार में वृद्धि

502. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न इस्पात उत्पादों विशेषत: हॉट रोल्ड क्वायल्स, टिन प्लेटों और इलेक्ट्रिकल स्टील प्लेटों के भंडार में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) मुख्य इस्पात उत्पादकां के पास दिनांक 1.1.95 और 1.1.96 को तप्त बेलित क्वायलों, टिन प्लेंटों और इलैक्ट्रीकल शीटों और कुल परिसज्जित इस्पात के भंडार निम्नानुसार थें :-

(हजार टन)

	मद	1.1.95 की स्थिति के अनुसार	1.1.96 की स्थिति के अनुसार
1.	तप्त बेलित क्वायलें/स्कैल्प	151	226
2.	इलैक्ट्रीकल शीटें	11	13
3.	टिन प्लेंटे	13	3
4.	कुल परिसज्जित इस्पात	900	1038

इस्पात के मूल्यन और विवरण पर से 16.1.1992 से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। इस्पात उत्पादकों ने माल सूची में कमी हेतु उचित कदम उठाए हैं और बाजार के अनुरूप नीति अपनाई है।

Revival of HFC and FCI plants

503. SHRIMATI CHANDRA-KALA PANDEY:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the present status of revival of HFC and FCI plants;

(b) whether the cabinet decision in April 1995 to revive HFC and FCI plants throuth Rs. 2207 crore package has been shelved;

(c) if so, why was the package announced without ascertaining the funding source;

(d) if not, the expected zero date for commencement of revival schemes; and

(e) the interest burden on HFC and FCI as on 31.3.91 vis-a-vis interest as on date?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (c) The revamp proposals formulated for submission of revival packages in respect of Hindustan Fertilizer Corporation Limited (HFC) and Fertilizer Corporation of India Limited (FCI) to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) were approved in principle by the government in April, 1995. In view of the fact that the revival packages envisaged an investment of Rs. 2201.13 crore (Rs. 464.93 crore for HFC and Rs. 1736.20 crore for (FCI) it was inter-alia decided to involve the Financial Institutions (FIs) in the financing of these packages in order to minimise the requirement of budgetary support. FIs have been directed to undertake reappraisal of the revival packages from the angle of techno-economic viability.

(d) Since implementation of revival packages is contingent on tying up of funding asignemnt and approval of the same by the BIFR, which is a quesi-judicial authority, it is not possible at this stage to indicate the expected zero date for commencement of implementation of revival packages.

(e) Excluding the penal interest on Government of India loans upto 31.3.91 at Rs. 282.84 crore for HFC and Rs. 137.53 crore for FCI, not provided for in the accounts, the interest burden on HFC and FC1 as on 31.3.91 and 31.3.95 was as under:—